

CFM/151

39

न्यायालय मानवीय राजस्व मण्डल, म०प्र० रवालियर

प्रकरण क्रमांक

१६ निगरानी

R-2298 PBR/98

भी १८८० का अभिभावक हारा आनंदित २६/१८८०
को प्रस्तुत
देवी अंक कोट
राजस्व म०प्र० र. रवालियर

२८/१८८०
२८/१८८०
२८/३८५
२८/१९२०

श्रीमान,

- निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-
- (१) यह कि आर बन्दोबस्त आयुक्त महोदय एवम् जिला बन्दोबस्त अधिकारी महोदय की आजाये कानून सही नहीं है है
 - (२) यह कि अपर बन्दोबस्त आयुक्त महोदय एवम् जिला बन्दोबस्त अधिकारी महोदय ने पुनर्स्थापन के संबंध में क्र्याधिक कठौर रूप अपनाया है ।
 - (३) यह कि आर बन्दोबस्त आयुक्त महोदय के विवादित आदेश के पद क्रमांक २ से यह स्पष्ट है कि जिला बन्दोबस्त अधिकारी महोदय के समान पुनर्स्थापन का आवेदन पत्र सम्यावधि में प्रस्तुत किया जा चुका था । प्रकरण मैं देखना यह था कि जिस दिन प्रकरण असम पैरवी में

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 2298-पीबीआर/1998 निगरानी

जिला भिण्ड

तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

३-४-१६

यह निगरानी अपर बंदोवस्त आयुक्त, म०प्र० ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 60/1994-95 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-7-1998 के विरुद्ध म०प्र० भू राजस्व संहिता, 1959 की 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक के अभिभाषक श्रीके०डी०दीक्षित एवं अनावेदक के अभिभाषक श्री ए०के०सिंघल को सुना गया तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं अपर बंदोवस्त आयुक्त, म०प्र० ग्वालियर के आदेश दिनांक 16-7-1998 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि बंदोवस्त अधिकारी, भिण्ड के समक्ष प्रचलित प्रकरण क्रमांक 74/93-94 निगरानी दिनांक 25-10-94 को अदम पैरवी में निरस्त हुई, जिसके पुर्वस्थापन हेतु धारा 35(3) के अंतर्गत दिया गया आवेदन भी आदेश दिनांक 5-6-95 को निरस्त किया गया। इस आदेश के विरुद्ध अपर बंदोवस्त आयुक्त, म०प्र० ग्वालियर के समक्ष अपील क्रमांक 60/1994-95 प्रस्तुत हुई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 16-7-1998 से अपील अमाब्य की गई। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत हुई है जिसा विचार करने

(M)

पक्षकारों
अभिभाषक
के हस्ताक्ष

प्र०क०२२९८-पीबीआर/१९९८ निगरानी

से स्थिति यह है कि म०प्र०भू राजस्व संहिता १९५९ की धारा ३५ में व्यवस्था की गई है कि :-

“धारा ३५(३) के आवेदन की अस्वीकृति होने पर अपील - केवल एक अपील का हक है - माननीय उच्च व्यायालय मध्य प्रदेश ने विनिश्चित किया है कि एक ही अपील ३५(४) के अधीन हो सकेगी - आगे छित्तीय अपील नहीं होगी, पुनरीक्षण नहीं होगी।”
(सौदान सिंह बनाम म०प्र०राज्य १९८६ रा.नि. १ = १९८६ म०प्र०ल००ज० ३०२ हा०को०)

उपरोक्त आधार पर प्रस्तुत निगरानी प्रचलन-योग्य नहीं पाये जाने से इसी-स्तर पर निरस्त की जाती है।

सदाचार